

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम० के० सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 36-दो/1991 विरुद्ध आदेश दिनांक
31.12.1990 पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग,
मुरैना - प्रकरण क्रमांक 241/1985-86 अपील

विश्वनाथ पुत्र हरविलास ग्राम सिरमोर का पुरा
मौजा विरहरुआ तहसील अम्वाह जिला मुरैना

-----आवेदक

विरुद्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन
- 2- श्रीचन्द्र पुत्र बीघाराम
- 3- श्रीमती कंठश्री पत्नि स्व. गोपीराम
निवासी सिरमोर का पुरा तहसील अम्वाह
जिला मुरैना मध्य प्रदेश

----अनावेदकगण

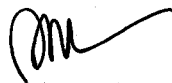
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक 1 के अभिभाषक पैनल लायर)
(अनावेदक 2,3 अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक २ - ११ - २०१५ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के
प्रकरण क्रमांक 241/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक
31.12.1990 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की
धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि हलका नंबर
28 तहसील अम्वाह के पटवारी ने तहसील न्यायालय में सूचना दी




कि आवेदक ने ग्राम रामपुर की आराजी नंबर 257 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर आवेदक ने अतिक्रमण किया है, कार्यवाही की जाय। नायब तहसीलदार अम्वाह ने आवेदक के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 41/85-86 अ 68 दर्ज किया तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदक की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 14-1-86 पारित किया तथा आवेदक पर रु. 500/- अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह के समक्ष अपील क्रमांक 38/85-86 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 15-4-86 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 241/1985-86 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31.12.1990 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

2/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने। अनावेदक क्रमांक 2 व 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

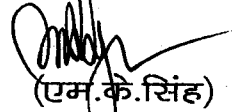
3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह सही है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में बचाव में स्वयं का दिनांक 26-10-85 को कथन दिया है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का उसे पूर्व में पट्टा दिया गया है तभी से वह काविज होकर खेती करता आ रहा है, किन्तु अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 12/1971-72 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-5-75 से पट्टा निरस्त कर दिया है एवं भूमि पूर्ववत् शासकीय अंकित हुई है, जिसके कारण आवेदक शासकीय भूमि पर अतिक्रमक होना स्वयं के कथनों से सिद्ध हुआ है और शासकीय भूमि पर अतिक्रमक को किसी प्रकार के स्वत्व एवं





स्वामित्व नहीं पहुंचते हैं जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमो में दिये गये तथ्यों पर प्रस्तुत तर्क व्यर्थ हैं और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह ने अपील क्रमांक 38/85-86 में पारित आदेश दिनांक 15-4-86 से तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा अपील क्रमांक 241/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 31.12.1990 से नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 14-71-86 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 241/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 31.12.1990 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी अस्वीकार की जाती है।



(एम.के.सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर